चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में

115 सीडब्ल्यूपी-3326-2023

निर्णय की तिथि: 24.04.2023

मनीषा और अन्य...याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य...प्रतिवादी

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में

कोरम: माननीय श्रीमान. जस्टिस सुवीर सहगल
वर्तमान: श्री राहुल सिंह, याचिकाकर्ताओं के वकील।
सुवीर सहगल जे. (मौखिक)

1. दिनांक 02.05.2022 के संलग्नक पी-1 के विवादित पत्र को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग करते हुए तत्काल याचिका दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को 5,000/- रुपये प्रति माह का मानदेय दिया गया है। हरियाणा राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी के अनुसार याचिकाकर्ताओं को वेतन देने के लिए उत्तरदाताओं को एक परमादेश जारी करने के लिए एक और प्रार्थना की गई है।

2.याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत आयुष्मान मित्र के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें करनाल में तैनात किया गया है। उनका कहना है कि दिनांक 02.05.2022, अनुबंध पी-1 के विशिष्ट दिशानिर्देशों के बावजूद, याचिकाकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है।

3. इसके विपरीत, विद्वान राज्य के वकील ने याचिका का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता संविदा कर्मचारी हैं और उन्हें सरकार द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना या निर्देश का लाभ नहीं मिल सकता है। उनके द्वारा CWP-25134-2022 शीर्षक में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.11.2022 के निर्णय पर भरोसा रखा गया है

सूरज और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

4. मैंने पक्षों के वकील को सुना है और उनकी संबंधित दलीलों पर विचार किया है।

5. सूरज मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ को एक समान मुद्दा पकड़ा गया था, जहां याचिकाकर्ताओं के समकक्षों ने मासिक मानदेय/पारिश्रमिक बढ़ाने का दावा करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। निम्नलिखित अवलोकन:-

6. केस फ़ाइल के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल हैं, जिन्हें असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के तहत हलफनामों के आधार पर नहीं माना जा सकता है।

7. यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं अनुबंध के आधार पर ली गई थीं। संविदा कर्मचारी के पास केवल रोजगार अनुबंध के चारों कोनों तक सीमित सीमित अधिकार हैं। अनुबंध के संदर्भ में संविदात्मक सेवाओं को जारी रखना और/या बंद करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है। मेरा विचार है कि अनुबंध का मामला होने के संक्षिप्त आधार पर, इस न्यायालय को अपने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

8. यह न्यायालय कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त करने के नियोक्ता के विवेक के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से परहेज करेगा।

9. याचिकाकर्ताओं को उचित वैकल्पिक उपाय खोजने की स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है, जैसा कि सलाह दी जा सकती है और कानून के तहत उपलब्ध है।"

6. उपरोक्त के मद्देनजर, सूरज के मामले (सुप्रा) में फैसले के बाद, याचिकाकर्ताओं को कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय, यदि कोई हो, का सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका खारिज की जाती है।

24.04.2023 सुवीर सहगल(जज)

शीतल

क्या बोल रहे हैं/तर्क कर रहे हैं: हाँ/नहीं

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ/नहीं